

श्री हरीश कुमार गांधार : अध्यक्ष महोदय मुझे मालूम हुआ है कि दो सबजेक्ट्स हैं।

अध्यक्ष महोदय : विजनेस के मुताबिक कहना है तो शुक्रवार को कहिएगा।

श्री हरीश कुमार गांधार : प्राइस राइज

MR. SPEAKER : Disallowed.

गंगवार जी, आप समझदार आदमी हो कर ऐसी जिद करते हैं। जब मैं ने आप को कहा है कि जो आप कहेंगे वह कर दूंगा और विजनेस ऐडवाइजरी कमेटी जो तय करेगी वह करूंगा; फिर भी आप जिद करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : It is not to be discussed here. It is for the Business Advisory Committee to decide. You are unnecessarily doing it.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात। आप अपने मੈम्बर को विजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में भेज दीजिएगा। या आप आइएगा, मैं आप को भोजन भी कराऊंगा, मिष्ठान भी खिलाऊंगा और जो कहेंगे वह करूंगा। न गवर्नमेंट विरोध कर रही है न अपोजीशन विरोध कर रहा है दोनों मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या करूं ? बहुगुणा जी, आप अपने मੈम्बरों को इतना भी नहीं समझा सकते ?

12.15 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to start an express train between Allahabad and Faizabad via Pratapgarh and Sultanpur.

श्री बी डी सिंह (फूजपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

उत्तर प्रदेश के महानगर इलाहाबाद में सुप्रसिद्ध तीर्थ-स्थान प्रयागराज स्थित है और इसी प्रकार फैजाबाद में अयोध्या। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से तीर्थ यात्री प्रयागराज जाते हैं। जो तीर्थ-यात्री प्रयागराज आते हैं उनमें अधिकांश अयोध्या भी जाना चाहते हैं। इस के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कई प्रमुख विभागों के मुख्यालय इलाहाबाद में होने के कारण फैजाबाद संभाग से भी बड़ी संख्या में लोग इलाहाबाद आते जाते रहते हैं। इलाहाबाद-फैजाबाद रेल मार्ग प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर जनपदों के मुख्यालयों से होकर गुजरता है। परन्तु इलाहाबाद-फैजाबाद रेलवे पर कोई दुर्तगामी यात्री गाड़ी नहीं चलने से यात्रियों को बड़ी ही कठिनाई एवं असुविधा का सामना करना पड़ता है। दोनों नगरों के बीच जो पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं वे कब छुटंगी कहां रुक जायेगी और कब अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचेगी, कोई भी बता नहीं सकता। इन परिस्थितियों में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि इलाहाबाद फैजाबाद के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जाय। इस संबंध में पहले भी इस सम्मानित सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन कर चुका हूँ। इस के अतिरिक्त अन्य माध्यमों

(श्री बी. डी सिंह)

द्वारा भी जनता द्वारा बराबर मांग होती रही है। परन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल सका है। एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का यदि आकलन कराया जाये तो वे पूर्णतया अनुकूल ही होंगी।

अतएव मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद फैजाबाद के बीच शीघ्र ही एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाय जो बीच में केवल प्रताप गढ़ एवं सुल्तानपुर जनपदों के मुख्यालयों पर रुके।

श्री मनीराम वागड़ी : अध्यक्ष महोदय, 377 का जवाब मंत्री लोग नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देते हैं।

श्री राम विलास पासवान : कभी नहीं मिलता है।

MR. SPEAKER : I got the information. Out of 382, 268 had been replied.

(ii) *Need to provide drinking water in Sahdol, Satna and Rewa districts of Madhya Pradesh.*

श्री दलवीर सिंह (शहडोल) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत में निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से आधे से अधिक जिलों में वर्ष न होने के कारण उन जिलों में अकाल की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेषकर रीवा संभाग में उन सभी चारों जिलों में वर्षा न होने से पीने के लिए पानी की विशेष कठिनाई अभी से उत्पन्न हो गई है। शुरु में थोड़ा वर्षा होने से जो बोनी

की गई थी वह भी सूख गई है इस से सूखे की स्थिति स्पष्ट सामने दिखाई दे रही है।

अतः भारत सरकार से निवेदन है कि रीवा संभाग के उन सभी चारों जिलों, जिला शहडोल सीधी, सतना व रीवा के लिए राहत कार्य हेतु पर्याप्त राशि स्वीकृत की जावे व साथ ही म. प्र. शासन को निर्देश किया जावे कि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करे।

(iii) *Central assistance to Government of Rajasthan for repairing roads damaged by army exercises.*

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ :

प्रतिवर्ष सदियों में जनवरी एवं फरवरी में थल सेना का अभ्यास राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर बीकानेर एवं गंगा नगर जिलों में होता है, जिस में मिलिटरी के बड़े वाहनों जीप ट्रकों एवं ट्रैक्टरों आदि का प्रयोग होता है जिस के कारण प्रतिवर्ष राज्य की सड़कों का करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। थल सेना एवं सीमावर्ती सड़क संस्था उन क्षतिग्रस्त सड़कों की कोई मरम्मत एवं सुधार नहीं करती और राज्य भी सीमित साधनों के कारण उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार नहीं कर पाता जिस के कारण आवागमन बन्द हो जाता है और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। यह समस्या हर साल बनी रहती है।

इस बारे में मैंने लोक सभा प्रश्नों, एवं रक्षा मंत्री का ध्यान पत्रों द्वारा आकर्षित किया और गत वर्ष यानि 1983-84 में राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण के अधिकारियों एवं